संपादकीय

एक किसान अपने बच्चे से कहता है कि अच्छा पढ़ो और नौकरी करो नहीं तो मेरी तरह कष्ट भोगोगे

यह केवल एक अभागे पिता की एकमात्र चेतावनी नहीं है, बल्कि विकासशील देशों के लगभग सभी किसानों की वास्तविकता है। माता–पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे खेती करें। पूरे विश्व की सरकारें वर्ष 2008 से बढ़ते हुए खाद्य मूल्यों के कारण शहरी लोगों के असंतोष को दबाने के लिए ही शोर मचाती हैं। किसानों को केवल सस्ता अनाज उगाने वाले ही माना जाता है। भारत में प्याज का आयात इसलिए किया जाता है कि शहरी मतदाता सत्ताधारी सरकार को बढ़ती हुए खाद्य मुद्रा स्फीति के कारण सत्ता से बेदखल न कर दें किंतु सरकार किसानों को उनके उत्पादन पर मिलने वाले कम मूल्य के प्रति चिंतित नहीं है।

विडंबना यह है कि अनाज उगाने वाला ही भूखा, निर्धन रहता है और कुपोषण का शिकार है। इसमें परिवर्तन करना कभी आसान नहीं रहा है। यह एक ऐसी उलझन है जो सभी को मिलकर दूर करनी होगी। किंतु ये प्रयास खेती के क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। हम कहां से शुरूआत कर सकते हैं? हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसानों को शामिल करना चाहिए। पशुपालन, मछलीपालन और कुक्कुट पालन से छोटे किसान परिवारों की आय में जल्दी वृद्धि हो सकती है। इसके लिए हमें न्यूनतम जोखिम, मौसम की भविष्यवाणी, परिवहन बाजार तक पहुंच, कारगर नियम लागू करना, सड़क संपर्क, फसल के अंतराल को कम करने जैसे कुछ क्षेत्रों में कदम उठाने होंगे। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने की और सीमाओं के आर–पार व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। इन्हें लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है किंतु ऐतिहासिक अनुभव हमें अनुचित करारों के फंदे से सावधान रहने को भी कहता है।

विश्व में प्रमुख जिंसों के भाव अमीर देशों के किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं जिनसे जिन्स के भाव इतने गिर जाते हैं कि निर्धन देशों के किसान हानि उठाते हैं क्योंकि उनका उत्पादन सस्ता हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, कृषि अनुसंधान और विकास में स्थानीय निवेश भी लाभकारी सिद्ध नहीं होता जिसकी सकारात्मक परिवर्तन करने में प्रमुख भूमिका है। उलझन और जटिल हो जाती है जिससे भारतीय अनुसंधान पद्धति के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला पैसा कम होने लगता है जो एक विशेष योजना की वकालत करने, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और चापलूस सरकारी अधिकारियों के कारण होता है। आप अपनी सहायता के लिए क्या करेंगे?